



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (प्रसाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 3 अगस्त, 2005/12 भावन, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

चम्बा-176310, 6 जुलाई, 2005

क्रमांक पंच-चम्बा-2004-983-993.—चूँकि पंचायत निरीक्षक कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, चम्बा की जांच रिपोर्ट संख्या 5454, दिनांक 30-3-2005 द्वारा रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि श्री राकेश कुमार, वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत राजपुरा, विकास खण्ड चम्बा मास अप्रैल, 2004 से 8-12-2004 तक कुल सत्तरह बैठकों में से तेरह बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

क्रम सं०	मास	दिनांक	बैठकों में अनुपस्थित/उपस्थित
1	2	3	4
1.	अप्रैल, 2004	8-4-2004 24-4-2004	अनुपस्थित उपस्थित
2.	मई, 2004	8-5-2004 24-5-2004	उपस्थित उपस्थित
3.	जून, 2004	8-6-2004 24-6-2004	अनुपस्थित उपस्थित

1	2	3	4
4.	जुलाई, 2004	8-7-2004 24-7-2004	अनुपस्थित अनुपस्थित
5.	अगस्त, 2004	8-8-2004 24-8-2004	अनुपस्थित अनुपस्थित
6.	सितम्बर, 2004	8-9-2004 24-9-2004	अनुपस्थित अनुपस्थित
7.	अक्तूबर, 2004	8-10-2004 24-10-2004	अनुपस्थित अनुपस्थित
8.	नवम्बर, 2004	7-11-2004 24-11-2004	अनुपस्थित अनुपस्थित
9.	दिसम्बर, 2004	8-12-2004	अनुपस्थित

जैसा कि अधिनियम में प्रावधान है कि पंचायत या इसकी समितियों (कोई भी पंचायत अधिकारी) की लगानार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है या पंचायत की स्वीकृति के बिना छः मास की कालावधि के दौरान की गई बैठकों की आधी संख्या में उपस्थित होता है।

उपरोक्त के अन्तर्गत इस कार्यालय-के पत्र संख्या पंच-चम्बा-2004-661-68, दिनांक 18-5-2005 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिया गया था परन्तु 15 दिनों का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी वह प्राप्त नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट होता है कि आपको इस बारे कुछ नहीं कहना है।

अतः मैं, चमन सिंह (हि० प्र० से०), उपायुक्त, चम्बा पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (ख) व उप-धारा 2 में प्राप्त है श्री राकेश कुमार, वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत राजपुरा को पद के अयोग्य घोषित करता हूँ व सदस्य वार्ड राजपुरा के पद पर जनहित में बन्धे रहना समाप्त करता हूँ तथा वार्ड सदस्य पद को रिक्त घोषित करता हूँ यदि उनके कब्जे में पंचायत का कोई भी अभिलेख, धन या सम्पत्ति हो तो ऐसे अभिलेख, धन या सम्पत्ति को पंचायत सचिव को सौंप दें।

चमन सिंह
उपायुक्त,
चम्बा, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू (हि० प्र०)

कार्यालय आदेश

कुल्लू, 21 जून, 2005

संख्या पी सी एच (कु०) त्यागपत्र/रिक्त स्थान 1341-46. - यह कि खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू ने अपने पत्र संख्या 2150, दिनांक 13-4-2005 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि उनके विकास खण्ड की ग्राम

पंचायत तेगुबेहड़ के बाई 2 से निर्वाचित सदस्य सुश्री शम्मी बोध की दिनांक 26-2-2005 को मृत्यु हो जाने के कारण ग्राम पंचायत तेगुबेहड़ के सदस्य का पद रिक्त हो गया है। जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत तेगुबेहड़ के पालिगी प्रस्ताव दिनांक 26-3-2005 में की गई है।

अतः मैं, एच० आर० चौहान, उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) व (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्राम पंचायत तेगुबेहड़, विकास खण्ड कुल्लू में सदस्य का पद उपरोक्त दर्शाई गई दिनांक से रिक्त घोषित करता हूँ।

एच० आर० चौहान,
उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, किन्नौर स्थित रिकांग पिओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

रिकांग पिओ, 6 जुलाई, 2005

संख्या कन्नर-पंच-निर्वाचन-775/4194-99.—यह कि श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री राम कृष्ण सदस्य पालिगी वाई नं० 3 ग्राम पंचायत पौण्डा, तहसील निचार, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने आंगन बाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्ति के कारण दिनांक 6-5-2005 को अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है। जिनका त्याग-पत्र हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130(1) तथा सामान्य नियम, 1997 के नियम 135 के अन्तर्गत विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा 6-5-2005 को स्वीकृत किया गया।

अतः मैं, सतीश शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, किन्नौर स्थित रिकांग पिओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश, पालिगी वाई नं० 3 ग्राम पंचायत पौण्डा, तहसील निचार, जिला किन्नौर के पद को रिक्त घोषित करता हूँ।

सतीश शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
किन्नौर स्थित रिकांग पिओ, जिला किन्नौर,
हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय उपायुक्त मण्डो, जिला मण्डो, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

मण्डो, 13 जुलाई, 2005

संख्या पी०सी०एन०-एम०एन०डी०/2004-3130-34.—यतः श्रीमति विजय लक्ष्मी प्रधान, ग्राम पंचायत चोलथरा, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डो (हिमाचल प्रदेश) के विरुद्ध माननीय उप-मण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, सरकाराट द्वारा "आई० आर० डी० पी० का जूठा व फर्जी प्रमाण-पत्र तैयार करने, जिसे उन द्वारा रोजगार कार्यालय, सरकाराट में प्रस्तुत किया गया, ताकि उनका नाम आई० आर० डी० पी० श्रेणी में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापिका के पद के लिये सरकारी नौकरी हेतु निदेशक शिक्षा विभाग को भेजा जा सके" बारे लगे आरोप में दोषी पाया गया है तथा इस बारे भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 420, 468 तथा 471 के तहत मामला माननीय न्यायालय में दाखल है।

यह कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1860 के अध्याय XVII व XVIII धारा 420, 468 एवं 471 के अन्तर्गत उक्त श्रीमति विजय लक्ष्मी प्रधान, ग्राम पंचायत चौलथरा, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप निर्धारित हो चुके हैं।

और यह कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (1) (क) के प्रावधान अनुसार जिस पंचायत पदाधिकारी के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1860 के अध्याय XVII तथा XVIII के अन्तर्गत किसी मामले में आरोप निर्धारित किये जा चुके हों उसे उसके पद से निलम्बित किया जा सकता है।

अतः मैं, मुभाशीश पाण्डा (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (1) (क) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रीमति विजय लक्ष्मी प्रधान, ग्राम पंचायत चौलथरा, विकास खण्ड, धर्मपुर, जिला मण्डी को निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में उनका स्पष्टीकरण इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के 15 दिनों के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। नियत अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा इस सम्बन्ध में नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर दी जायेगी।

मुभाशीश पाण्डा,
उपायुक्त मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

शिमला-1, 12 जुलाई, 2005

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (4) 6/2004-3232-36.—यह कि राजकीय उच्च पाठशाला खड़ाहण, उप-तहसील ननखड़ी, विकास खण्ड रामपुर की मुरम्मत के लिये खण्ड विकास अधिकारी रामपुर के कार्यालय से प्राकृतिक आपदा (राहत कोष) मद से मु0 40,000/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से खण्ड कार्यालय द्वारा मु0 37,085/- रुपये की राशि पंचायत को अदा की गई।

यह कि उक्त राशि के सही ढंग से उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय नागरिकों द्वारा सरकार को पत्र लिखकर शिकायत की गई कि प्रधान, ग्राम पंचायत खड़ाहण द्वारा उक्त राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है।

यह कि उक्त शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त वास्तविकता जानने हेतु खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर से छानबीन/जांच करवाई गई तथा जांच के उपरान्त पाया गया कि प्रधान, ग्राम पंचायत खड़ाहण द्वारा स्कूल भवन की मुरम्मत का जो कार्य किया गया है का वास्तविक मूल्यांकन मु0 16,699/- रुपये का हुआ है जबकि प्रधान द्वारा इस कार्य पर मु0 37,085/- रुपये का व्यय किया दर्शाया है। इस तरह प्रधान द्वारा मु0 20,386/- रुपये का दुरुपयोग/गवन किया गया है।

अतः मैं, एस० के० बी० एस० नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित अधिनियम), 2005 की धारा 145 (ग) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 (1) (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, श्री दिला राम, प्रधान, ग्राम पंचायत खडाहण, विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला को इस आशय सहित कारण बताओ नोटिस जारी करता हूँ कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर 12.50% प्रतिशत ब्याज सहित उक्त राशि पंचायत में जमा कर अनुपालना रिपोर्ट खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर के माध्यम से इन कार्यालय को प्रेषित करे अन्यथा यह समझा जायेगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और उनके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम, 1994 की उक्त धारा के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

एस० के० बी० एस० नेगी,
उपायुक्त,
शिमला, जिला शिमला (हि० प्र०)।

